



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 419 राँची, मंगलवार 11 भाद्र 1936 (श०)
2 सितम्बर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

14 अगस्त, 2014

विषय: राज्य के मूक-बधिर सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता की स्वीकृति का प्रस्ताव।

संख्या-6/एस-1(न्या.मा.)-13/2012/2916/वि०--राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप केन्द्रीय वेतनमान सेवाशर्त सहित अन्य सुविधायें प्रदान करने के बिन्दु पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। उक्त के आलोक में 6th PRC के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28 फरवरी, 2009 के द्वारा केन्द्रीय वेतनमान महँगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता (राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद) की स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय आदेश संख्या-21(2)/2008- E-II (B) दिनांक 29 अगस्त, 2008 के द्वारा पूर्व के कार्यालय आदेश संख्या 21(1)/97- E-II (B) दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 के द्वारा की गई व्यवस्था को बरकरार रखते हुए, रिट याचिका (सिविल) संख्या 107/2011 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 12 दिसम्बर, 2013 के न्यायादेश के अनुपालन में मूक और बधिर कर्मियों को भी परिवहन भत्ता सामान्य दर से दुगुनी दर से अनुमान्य किया गया है। 6th PRC के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रावधान राज्य के मूक और बधिर कर्मियों के लिए लागू नहीं किया जा सका है।

2. पंचम वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के पत्र सं. 7663/वि.(2), दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 के द्वारा राज्य में नेत्रहीन एवं विकलांग सरकारी सेवकों को दुगुनी दर से परिवहन भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 395/वि. दिनांक 16 फरवरी, 2013 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय वाद संख्या 6011/2011 में दिनांक 9 जनवरी, 2012 को पारित न्यायादेश एवं छठे केन्द्रीय वेतनमान में नेत्रहीन एवं विकलांग कर्मियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू परिवहन भत्ता के अनुरूप राज्य सरकार के नेत्रहीन तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मियों को कतिपय शर्तों के साथ परिवहन भत्ता अनुमान्य किया गया है।

4. वाद संख्या 107/2011 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 12 दिसम्बर, 2013 के न्यायादेश के अनुपालन में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय आदेश संख्या- 21(2)/2008- E-II (B) दिनांक 19 फरवरी, 2014 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा पूर्व के कार्यालय आदेश संख्या 21(1)/97- E-II (B) दिनांक 29 अगस्त, 2008 के पैरा 2(i) दृष्टिहीन और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ता का लाभ तत्काल प्रभाव से केन्द्र सरकार के मूक और बधिर कर्मचारियों को भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बशर्ते कि सरकारी सिविल अस्पताल के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष की सिफारिश विभागाध्यक्ष को प्राप्त हो और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का०ज्ञा० के साथ पठित 31 अगस्त 1978 के का०ज्ञा० सं० 19028/1/78- IV (B) (छाया प्रति संलग्न) में उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी हों यथा प्रमुख शर्तें निम्न हैं :-

राज्य सरकार के मूक और बधिर कर्मचारियों को निम्न शर्तों के साथ परिवहन भत्ता अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है:-

- (क) मूक और बधिर कर्मचारियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि., दिनांक 28 फरवरी, 2009 की कंडिका 15(c) में अंकित शर्तों के साथ राँची, जमशेदपुर तथा धनबाद शहरों के लिए अंकित दरों से दुगुनी दरों पर परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ख) सरकारी सिविल अस्पताल के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित बोर्ड की सिफारिश विभागाध्यक्ष को प्राप्त हो एवं यह भत्ता विभागाध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर ही अनुमान्य होगा। मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्रों पर Issue No. होना अनिवार्य है। यह सभी विपत्र का अंग रहेगा एवं Service Record में इसकी प्रविष्टि करते हुए संधारण भी किया जायेगा।
- (ग) सरकारी वाहन की सुविधा प्राप्त कर्मियों को परिवहन भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- (घ) यह भत्ता (i) 30 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश (ii) पारगमन काल एवं (iii) निलम्बन अवधि में अनुमान्य नहीं होगा।

5. इस परिवहन भत्ता की स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा दी जायेगी। संबंधित सरकारी सेवकों से अलग-अलग आवेदन पत्र प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेश में कंडिका-4 (ख) का स्पष्ट उल्लेख रहेगा तथा प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति आदेश का अंग रहेगा। आदेश पर कर्मचारी का GPF/CPF/PRAN No. एवं अन्य Details रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि नियुक्ति के समय से विकलांग हैं या सेवाकाल में विकलांगता प्राप्त किये हैं।

6. यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगे।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2719/वि. दिनांक 30 जुलाई, 2014 के क्रम में दिनांक 7 अगस्त, 2014 की बैठक के मद सं. 21 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव।
